Ichapurs and Golf Green-I Wells, drilling operations have been stopped in the Bengal basin;

(b) if so, when the drilling for Ichapur type of oligocene prospect will be resumed in Ranaghat, the Golf Green type of prospect will be resumed in the vicinity of the hinge zone and Chandkuri type of paleocene prospect will be resumed in Contai area; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) No, Sir; While in Ichapur-I, noncommercial hydrocarbon indication was found, only traces of oil in water during testing was observed in Golf-Green-1. Currently, drilling operations are continuing in West Bengal for coal-bed methane.

(b) and (c) Drilling of 48 wells (41 in onland and 7 in offshore) have yielded highly discouraging results. However exploratory efforts are being continued by way of 2D and 3D seismic surveys. Simultaneously, the geoscientific data generated so far is being re-assessed. Further exploratory drilling can be taken up only after firming up of the highest quality prospects.

Charges of Corruption Against Ministers

2508. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a number of allegations of corruption have been made against the Ministers in the new cabinet;

(b) if so, what is the total number of such Ministers;

(c) whether the Prime Minister has enquired into the allegations;

(d) if so, to what extent they have been found true;

(e) what action has been taken on these allegations; and

(f) whether the Prime Minister is considering to replace those Ministers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI. S.R. BALASUB-RAMONIYAN): (a) to (f) Based on some Press Report, some complaint has been made against some Minister and the complaint is under scrutiny.

Streamlining the Functioning of Central Electricity Authority

2509. SHRI BANGARU LAXMAN: SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to streamline the functioning of the Central Electricity Authority,

(b) if so, whether the Committee on Tariff Regulation also proposes to give its recommendations in this regard; and

(c) if so, the details in this regard and to what extent the CEA would be made more functional?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Steps to steamline the functioning of Central Electricity Authority have been initiated in the Ministry of Power.

(b) Ministry of Power has not constituted any Committee on Tariff Regulations.

(c) The recommendations of a consultant in this regard are awaited, whereafter specific steps would be taken to bring about the requisite changes.

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किए गए आवास

2510. श्री अ॰ पी॰ कोहली: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक निर्मित किए गए आवासों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त में से कितने आवासों में लाभार्थी बस गए हैं और कितने आवास अभी भी खाली पड़े हैं; और

(ग) इस योजना पर इसके प्रारम्भ होने से लेकर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) चल रही आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक निर्मित आवासों की संख्या 1920899 है।

(ख) योजना आयोग द्वारा कराये गए अध्ययनों के अनुसार, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 86 प्रतिशत से भी अधिक आवासों का कब्जा ले लिया गया और उनमें लोग रह रहे थे तथा उन परिवारों के लगभग 84 प्रतिशत ने उनके आबंटित किये गए आवासों के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया। कुछ मामलों में, लाभार्थियों ने आवासों को कब्जे में नहीं लिया क्योंकि आवास मुख्य बसावट अथवा कार्य-स्थल से काफी दूर थे। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये गए कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास गांव के समीप हों और अधिक दूरी पर न हों ताकि रक्षा एवं सुरक्षा, कार्यस्थल की समीपता तथा समाज के बीच उनकी सम्पर्कता को सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) 1985-86 में इन्दिरा आवास योजना के शुरू होने से लेकर अब तक, 3771.47 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया गया है जिससे 3015964 आवासों को बनाया गया है।

दिल्ली गोल्फ क्लब के पट्टे का नवीनीकरण

2511. **श्री महेश्वर सिंह:**
श्री संजय डालमिया:

क्या प्रधान मंत्री 12 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2590 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली गोल्फ क्लब को दी गई भूमि के संबंध में पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि को और किस अवधि तक नवीकृत किया गया है;

(ग) क्या गोल्फ क्लब द्वारा निर्धारित दरों पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह भुगतान कब किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जी; हां।

(ख) दिनांक 1.1.1991 से 31.12.2010 तक के लिए पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्लब ने विचाराधीन अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क अदा कर दिया है।

पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2512. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमोत्तर क्षेत्र, विशेषकर गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इस क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना में मुख्य कठिनाइयां क्या-क्या हैं;

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में ऐसे और अधिक उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ङ) गुजरात में स्थापित किए जाने वाले अधिक संभावना वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1992-93) के अनुसार गुजरात राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 1,178 फैक्ट्रियां थी। खाद्य व्यापार और उद्योग महासंघ की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में अधिक लागत के कारण सीमित बाजार; कर और शुल्क; सुदृढ़ बागवानी आधार की कमी; तकनीकी जनशक्ति की कमी के बीच तालमेल की कमी; बुनियादी समर्थन का अभाव तकनीकी जनशक्ति की कमी आदि जैसी कठिनाइयां उद्योग के